पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड होंगी सौ करोड़ से अधिक की परियोजनाएं

राब्यू, लखनऊ : प्रदेश में अब सौ करोड़ से अधिक की परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से ही लागू की जाएंगी। सभी विभाग परियोजनाओं को इस पोर्टल पर अपलोड करेंगे व इससे केंद्र व राज्य सरकार को पता होगा कि कौन सी परियोजना किस राज्य में किस कीमत पर चालू होने वाली हैं। वहां के नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप से अनुमोदन कराने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 15 फरवरी तक अपनी-अपनी परियोजनाओं को इस पोर्टल पर अपलोड करें।

पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से योजनाएं बनाने से अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। किसी परियोजना का पहले डीपीआर बनाने में करोड़ों का खर्च आता है। अब इसके माध्यम से यह पता चल सकेगा कि पहले इस तरह की परियोजना कहां किस राज्य में चल रही है। अगर ऐसी परियोजना पहले से चल रही है तो फिर उसे नई जरूरतों के अनुसार संशोधित भी किया जा सकेगा। यही नहीं इससे धान व गेहूं खरीद केंद्र खोलने के लिए उपयुक्त लोकेशन की पहचान आसानी से होगी। रजिस्ट्री व जमीन की खरीद फरोख्त में आसानी होगी।